6. Surveys for updating of land records are being done in a number of States. Some States have also opted for other methods of updating of land records.

7 Computerisation of land records has been taken up on pilot project basis in 19 States which are in various stages of implementation.

8 Land reforms is a multifacet programme. States have achieved different levels of success in different programmes There is no single commonly accepted index of back wardness in land reforms.

9 The Government of India periodically reviews implementation of land reforms in the States. In the recently concluded Conference of Revenue Ministers of States held on 14th March 1992 at New Delhi, the States have undertaken to speed up distribution of ceiling surplus land within a specified time frame.

देश में फालतू भूमि

4021. **श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि-अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन देश में घोषित की गई फालतू भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस फालतू भूमि में से दिसंबर, 1991 तक कितनी भूमि का वितरण कर दिया गया है ;

(ग) उक्त भूमि के वितरण से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के ऐसे लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी कितनी है, जिन्हें इस भूमि का आबंटन किया गया है, और

(घ) शेष भूमि का आवंटन न किए जाने के लिए क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)** ।

(घ) मुख्य कारण हैं : भूमि का मुकदमेबाजी में फंसा होना, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित/हस्तान्तरित होना, खेती के लिए उपयुक्त न होना तथा अन्य विभिन्न कारणों का होना ।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

सूचना दिसम्बर, 1991 तक है

क्रमांक	राज्य	फालतू घोषित क्षेत्र	वितरित किया गया क्षेत्र	निम्नलिखित वर्गों के लाभार्थियों की संख्या	
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	729394	463275	177225	68162
2.	असम	610370	432141	35139	33134
3.	बिहार	474621	268149	190934	35559
4.	गुजरात	251528	126861	12469	12507

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	121409	113047	17642	0
6.	हिमाचल प्रदेश	284053	3340	2934	261
7.	जम्मू व कश्मीर	456000	450000	0	0
8.	कर्नाटक	275298	113973	17742	777
9.	केरल	133354	62941	57904	7128
10.	मध्य प्रदेश	294570	176200	19788	25707
11.	महाराष्ट्र	704329	524645	39195	26283
12.	मणिपुर	1830	1682	96	72
13.	उड़ीसा	173926	146100	42623	46568
14.	पंजाब	138090	101838	10048	0
15.	राजस्थान	618712	433738	26688	11648
16.	तमिल नाडु	179767	143537	54480	97
17.	त्रिपुरा	1995	1599	256	359
18.	उत्तर प्रदेश	531755	361527	212656	711
19.	पश्चिम बंगाल	1262777	913389	741094	384033

Most Backward Areas

4022. SHRI JAGADISH JANI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have identified 100 most backward areas for their all rural development ;

(b) if so, the State-wise details of those areas ;

(c) the details of the schemes prepared for the development of those areas; and

(d) the funds earmarked for their development ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

मध्य प्रदेश में पेयजल

4023. श्री लालूराम अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य के अधिकांश भागों में प्रदूषित पेय जल के कारण "नारू" नाम की महामारी फैल गई है ; और

(ख) इन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में गिनी कृमि से प्रभावित 20 गांवों में गिनी कृमि से प्रभावित 120 मामले थे ।

(ख) और (ग) इन 26 गांवों में सभी सीढ़ीदार कुओं को स्वच्छ कुओं में बदल दिया गया है । पूरे राज्य में, 3217 सीढ़ीदार कुओं में से 3172 कुओं को स्वच्छ जल स्रोतों में बदल दिया गया है । स्वच्छ पेयजल की सप्लाई, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार, घरेलू/पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा विकास आदि के लिए